<u>राज्य सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 4289

04 अप्रैल, 2018 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय इस्पात नीति के अंतर्गत इस्पात उत्पादन का लक्ष्य

4289. श्री टी. जी. वेंकटेशः

डा. प्रदीप कुमार बालमुचूः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति के अंतर्गत 182 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लक्ष्यों के अनुसार इस लक्ष्य को अगले चौदह वर्षों में प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि इस्पात की स्थिर मांग के कारण इस क्षेत्र की ऋण स्थिति बदतर हो गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा मांग के अनुसार इस्पात उत्पादन बढ़ाने हेतु कौन-से कदम उठाए जा रहे हैं?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क): सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत 182 मिलियन टन इस्पात क्षमता का कोई लक्ष्य तय नहीं किया है।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): भारतीय इस्पात उद्योग अप्रैल, 2014 से दिसंबर, 2015 के दौरान कई चुनौतियों का सामना कर रहा था और इससे घरेलू इस्पात की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके फलस्वरूप घरेलू इस्पात उत्पादकों को बिक्री से कम वसूली हुई है। कम वसूलियों और परिणामस्वरूप इस्पात कंपनियों को हुई हानियों से उनकी ऋण चुकाने की क्षमता क्षीण हुई है, जिससे क्षेत्र में ऋण की समस्या बढ़ गई है।

(ङ): सरकार की 'मेक-इन-इंडिया' पहल विनिर्माण और अवसंरचना पर बल प्रदान करती है जिसके अंतर्गत देश में इस्पात की माँग और खपत पर जोर प्रदान किया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 और सरकारी खरीद में घरेलू निर्मित लोहा और इस्पात (डीएमआई एंड एसपी) को वरीयता प्रदान करने की नीति अधिसूचित की है जो इस्पात के घरेलू उत्पादन और खपत में सुधार लाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती हैं।

*****